

वह कच्छ बचाट के सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख न करें क्यों कि वह वियम 343 के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर सकतीं। दूसरे इस प्रस्ताव पर मत विभाजन नहीं किया जाना चाहिये।

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी):**

सभा में की गई चर्चा से यह आभास मिलता है कि हमारे विपक्षी मित्रों में अब यह साहस नहीं रहा जो गतवर्ष था। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न दलों के और विभिन्न विचार धाराओं वाले संयुक्त मोर्चे एक-एक कर के टूट गये हैं। इसके लिये उन्होंने कांग्रेस दल को दोषी ठहराया है किन्तु वास्तविकता यह है कि उनको अपने बारे में गलत फहमियाँ थीं। वह उनकी अपनी ही कमजोरियों और परस्पर विरोधी बातों ने दूर कर दीं।

आज देश को बहुत गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ की सभा में चर्चा भी की गई है। देश की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। देश की सुरक्षा का प्रश्न किसी दल, प्रदेश या स्थान का मामला नहीं है। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर कुछ भावविग प्रदर्शित किया गया है। ऐसे समय में जब हमारे नवयुवक और पुराने उपद्रवकारी गोहाटी, मेरठ, राँची, मद्रास और भारत के अन्य भाग में उपद्रव कर रहे हैं, मैं इस भावविग का स्वागत करती हूँ।

चौथी संसद् के सम्मुख मुख्य समस्या भारत की एकता और अखंडता को बनाये रखना है। हमारा सबका यह कर्तव्य है कि हम दायित्व को निभायें और मतभेदों का सड़क पर हल करने के लिये न ले जा कर विचार-विनिमय द्वारा हल करें।

एक वर्ष पूर्व जब चुनाव के परिणाम घोषित किये गये थे तो विश्व को भारत की स्थिरता के सम्बन्ध में शंका होने लगी थी। यदि देश में स्थिरता है तो यह विरोधी दलों के अजीब गुटों के कारण नहीं बल्कि इस कारण से है कि केन्द्रीय सरकार स्थिर और मजबूत है और वह राज्यों की अस्थिरता को भी पूरी तरह संभालने की शक्ति रखती है। हमने यह आशा की थी की सत्ता धारण करने और अधिक उत्तरदायित्व निभाने का जो अवसर विरोधी दलों को मिला है उससे उन्हें और अधिक जिम्मेदार बनने का अवसर मिलेगा। परन्तु, दुर्भाग्य से हमारी आशाएँ पूरी नहीं हुईं। हम विभिन्न सरकारों का स्वागत करते हैं। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि ये लोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि में लगे हुए हैं और वह विभिन्न राज्यों में अपने ही सहयोगियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं हिचकते। कुछ दल तो अपनी सब असफलताओं के लिये केन्द्र को ही दोषी ठहराते हैं।

इस वर्ष प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। इसके साथ ही हमें अनगिनत किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जो सहयोग दिया उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। हम यह चाहते हैं कि ऐसी ही रिकार्ड फसल अगामी वर्षों में भी हो। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं है। हमारी सबसे गम्भीर समस्याओं में एक खाद्य समस्या है। हम वसूली तथा उत्पाद नबढ़ाने के अपने प्रयत्नों में कभी नहीं करेंगे। हम दो लाख पम्प सैट मंगा रहे हैं और 32,000 नजरूप लगा रहे हैं। अगामी वर्ष हम 17 लाख टन उर्वरक की व्यवस्था करेंगे जब कि इस वर्ष हम केवल 13 लाख टन

की व्यवस्था कर पाये। हमारा यही प्रयत्न है कि जैसे प्रयत्न हम कृषि में कर रहे हैं वैसे ही प्रयत्न हम और क्षेत्रों में करते रहें। हमारे द्वारा किये गये कुछ समझौतों से इंजीनियरिंग उद्योग में सहायता मिलेगी।

शोषण ही बजट प्रस्तुत किया जायेगा। मेरे सहयोगी उप प्रधान मंत्री ने आज प्रातः आपके सामने आर्थिक सर्वेक्षण का वीरा खा जिस पर आप अभी चर्चा करेंगे। आज देश में बेकारों को बहुत बड़ी समस्या है विशेषकर इंजीनियरों की। परन्तु इंजीनियरों का होना अच्छा है क्यों कि पूँजी तथा सामान तो प्राप्त हो सकता है परन्तु बुद्धि-जीवियों का प्राप्त होना कठिन है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र के कारखानों का उल्लेख किया है। परन्तु उन्हें भी अब विवित हो गया होगा कि सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने की नीति ठीक ही थी क्यों कि जब गत वर्षों में देश पर आक्रमण हुआ तो इनके महत्व का पता चल गया। फिर भी इनमें अकार्यकुशलता का होना ठीक नहीं है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल की एक उप-समिति के सामने है और सरकार का इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही सभा के सामने आ जायेगा।

हमारी योजना के रूप में विकास की नीति का समर्थन हुआ है। श्री रंगा का कहना है कि योजना से छुट्टी मिलनी चाहिए। मेरा उत्तर यह है कि देश को योजना से छुट्टी नहीं मिल सकती तथा जब तक हमारा दल सत्ता में है हम ऐसी छुट्टी नहीं करेंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सके, इसका हमें दुःख है। हम उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे अन्य अल्पसंख्यकों से भी ऐसी ही सहानुभूति है।

श्री विश्वनाथन ने कहा कि मुझे दूढ़ होना चाहिये। परन्तु यदि मैं उनकी बात मान कर उनके व्रत पर दूढ़ होती हूँ तो दूसरे कहेंगे कि मैं दूढ़ नहीं हूँ। मैंने वही किया है जो प्राश्नासन मेरे स्वर्गीय पिता तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिये थे। भाषा के बारे में अधिक बोझ तो केन्द्रीय सचिवालय पर पड़ेगा क्योंकि वह अनुवाद देगा। यह सच है कि अहिन्दी भाषी राज्यों के लोगों पर हिन्दी भाषी के लोगों की तुलना में अधिक बोझ पड़ेगा।

श्री रंगा तथा श्री सी० सी० देसाई ने मुझे परामर्श दिया है कि मैं त्याग-पत्र दे दूँ। श्री रंगा ने इसी प्रकार का परामर्श मेरे पिता जी तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया था। श्री सी० सी० देसाई को ऐसा परामर्श देने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह तो आई० सी० एस० में कार्य करते थे जब कि हमारे देशवासियों को जेल में रखा जाता था तथा फांसी पर लटकाया जाता था। बाद में यह व्यापार-व्यवसाय में लग गये।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इन्हें उच्च आयुक्त आपके स्वर्गीय पिता ने नियुक्त किया था। आपने ही इन लोगों को इनाम दिया तथा आप उन पर आश्रित थीं और हैं...

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह भी उसी प्रकार चुनाव जीत कर आये हैं जैसे दूसरे

सदस्य आये हैं। प्रधान मंत्री का यह गर-जिम्मेदारी का बयान है। किसी और विषय पर आप त्रोलिये, वरों कि ऐसा कहना ठीक नहीं है।

**श्रीमती इंदिरा गाँधी :** मैं तो केवल श्री रंगा की बातों का उत्तर दे रही थी। आई० सी० एम० के व्यक्तियों को सेवा तथा त्याग के राजनीतिक स्कूल में शिक्षा नहीं मिली है।

**श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।**

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम व्यवस्था के प्रश्न को सुनते हैं।

**श्री मुहम्मद इमाम :** मैंने प्रधान मंत्री का भाषण सुना है। प्रधान मंत्री को अपने भाषण में इन सदस्यों के प्रति नम्रता दिखानी चाहिये थी जिन्होंने सरकारी नीति का विरोध किया। परन्तु मुझे दुख है कि उन्होंने विपक्षी दल के सदस्यों पर आक्षेप लगाये हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मैं अवश्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे प्रधान मंत्री के उत्तर को सुनें। आपको सभा में बहुत बार अपने विचार करने के अवसर मिलेंगे। आपको विभिन्न प्रस्ताव सभा में लाने का अधिकार है।

**श्रीमती इंदिरा गाँधी :** जहाँ तक वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है चर्चा के दौरान वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं कही गई है। सम्मन्यतः वियतनाम और पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में बातें कही गई हैं और इनके सम्बन्ध में हमें अधिक कुछ नहीं कहना है। वियतनाम में चल रहे युद्ध से हम काफी दुखी हैं और इससे हमें बड़ी चिन्ता है। दक्षिण एशिया में जो घटनाएँ घटी हैं उनमें भी हम चिन्तित हैं। हमारा हमेशा ही यही मत रहा है कि इन समस्या का समाधान सैनिक बल द्वारा नहीं किया जा सकता। हम अभी भी यही बात कहते हैं कि सबसे पहले वियतनाम पर बमबारी रोकੀ जानी चाहिये और इसके बाद इस झगड़े को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाया जाना चाहिये।

पश्चिमी एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए हमने हमेशा कहा है कि प्रत्येक देश को शान्ति और सुरक्षापूर्वक रहने देना चाहिये।

हिन्द-महासागर में घटने वाली राजनीतिक तथा अन्य घटनाओं की ओर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के सब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण और सन्तोषजनक है। इन देशों की सुरक्षा और स्थिरता सैनिक गठ-बन्धनों पर नहीं बल्कि आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता पर आधारित है।

कच्छ पंचाट का प्रारम्भिक और अन्तिम भाग सरकार को प्राप्त हो गया है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं इन दस्तावेजों की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ। हम पंचाट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि इस बीच इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है अतः मैं सभा को यह सूचित करना चाहती हूँ कि न्यायधिकरण ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि दशमलव 84, सरदारपुर, बिहारबेट, करीमशाही, बारिवेया बेट, 'सर्फनेलबेट' विगोकोट गैडावेठ तथा नारायण बेट श्रंखला भारतीय सीमा में आते हैं और रहीम के बाजार का दक्षिण का कुछ इलाका जिसमें पिटोल बालुकून, कंचरकोट, घाटादानी तथा छाटवेठ के क्षेत्र आते हैं, पाकिस्तान का क्षेत्र माना है। जैसे ही जाँच पूरी हो जायेगी

एक और वक्तव्य दिया जायेगा। यदि हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय दिये गये वचनों को पूरा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा।

सड़कों पर हिंसात्मक उपद्रव करना एक गम्भीर मामला है। यह बात समझ में नहीं आती कि इतने थोड़े से लोग इतना उपद्रव कैसे कर सकते हैं जब कि अधिकांश लोग उनके साथ नहीं हैं। अतः इन अल्प-संख्यक हिंसात्मक लोगों के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में देश के राजनीतिक और हमारे नागरिकों की काफी जिम्मेदारी है।

इस सम्बन्ध में मैं सेनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूँगी। यह बात समझ में नहीं आती कि ये मेनाएँ कौन सी लड़ाइयाँ लड़ रहीं हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है वहाँ केवल एक ही लड़ाई है और वह है गरीबी के विरुद्ध युद्ध और उसके लिये केवल एक सेना की आवश्यकता है और वह है भारत के सभी लोगों की सेना। साम्प्रयदिकता और हिंसात्मक के आतंक से उत्पन्न स्थिति को दल, प्रदेश जाति से ऊपर समझना चाहिए। एक भारतीय आरम्भ से अन्त तक एक भारतीय है।

यह स्पष्ट है कि हम कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुकरण कर रहे हैं। वे नीतियाँ आज की आवश्यकता के अनुसार हैं। परन्तु विपक्षियों ने इन कठिनाइयों को बढ़ाया ही है। अभी भी समय है कि हमें राष्ट्रीय प्रश्नों को साथ बैठ कर, विचार-विमर्श कर हल करना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री नैयर द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 30 और 31 को सभा में मतदान के लिये रखूँगा :

**संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए**

*Amendments were put and negatived.*

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 80 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :

**लोक-सभा में मत विभाजन हुआ**

**The Lok Sabha Divided**

पक्ष में ..... 44

विपक्ष में ..... 141

**Ayes 44 Noes 141**

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

*The Motion was negatived*

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री मधु लिमबे द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 92 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :

**संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ**

*The amendment was put and negatived.*

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री मसानी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 98 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ :